

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू

चर्चा में क्यों?

8 फरवरी, 2022 को राजस्थान राज्य सरकार तथा नविशकों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख 5 हजार करोड़ के एमओयू एवं एलओआई पर हस्ताक्षर हुए तथा इनका आदान-प्रदान किया गया। इस नविश से प्रदेश में करीब 90 हजार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान अक्षय ऊर्जा नगिम के 5 सार्वजनिक उपक्रमों तथा नजीक क्षेत्र की कंपनियों के साथ 3 लाख 5 हजार करोड़ रुपए के 90 गीगावाट से अधिक क्षमता के एमओयू एवं एलओआई हस्ताक्षरित किये गए।
- इनमें एनटीपीसी की ओर से 40 हजार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, एनएचपीसी की ओर से 20 हजार करोड़ की लागत से 10 गीगावाट, सतलज जल वदियुत नगिम की ओर से 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से 10 गीगावाट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से 10 गीगावाट तथा एसईसीआई की ओर से 9 हजार करोड़ की लागत से 2 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू एवं एलओआई शामिल हैं।
- इसी प्रकार रिलायंस समूह की ओर से 1 लाख करोड़ की लागत से 20 गीगावाट, एक्ससि एनर्जी समूह की ओर से 37 हजार करोड़ की लागत से 28 गीगावाट सोलर पार्क, सोलर प्रोजेक्ट एवं 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैनुफैक्चरिंग एवं सुखवीर एग्रो समूह की ओर से 2 गीगावाट एवं 100 मेगावाट क्षमता (बायोमास) के अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू एवं एलओआई शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान को रनियूएबल एनर्जी का हब बनाने के लिये सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति-2019 तथा वडि एंड हाइब्रिडि एनर्जी पॉलिसी जारी की थी। नविशकों को अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिये रपिस-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, एमएसएमई एक्ट जैसे नीतितंत्र नरिणय लिये गए।
- इस अवसर पर एनएचपीसी के नदिशक वार्डके चौबे ने कहा कि एनएचपीसी राजस्थान में 50 मेगावाट के वडि पावर प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम कर रहा है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एनएचपीसी 10 हजार मेगावाट क्षमता उत्पादन के लिये 20 हजार करोड़ रुपए का नविश करेगी।